

मज़दूर एकता लहर



हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़ढ़ पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख्बार



ग्रंथ-36, अंक - 19

अक्टूबर 1-15, 2022

पाक्षिक अख्बार

कुल पृष्ठ-4

कृषि का संकट और समाधान

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित मीटिंग

मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) की हुये मीटिंग की शुरुआत की कि "कृषि का संकट समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करता है और मज़दूर वर्ग के लिए यह एक बहुत चिंता का विषय है।" वे 11 सितंबर को "कृषि का संकट और समाधान" विषय पर आयोजित एक ऑनलाइन मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे।

मीटिंग में आमंत्रित वक्ता थे – मज़दूर एकता कमेटी के सचिव श्री बिरजू नायक, भारतीय किसान यूनियन एकता (डकॉंदा) के अध्यक्ष श्री बूटा सिंह बुर्ज गिल, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.ई.एफ.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र दूबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. बी. सेठ और भारतीय रेलवे लोको रनिंगमैन ऑर्गनाइजेशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय पांधी।

संतोष कुमार ने वक्ताओं का परिचय देते हुए बताया कि श्री बूटा सिंह जी, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा एक साल से अधिक समय तक चलाये गये

ऐतिहासिक विरोध संघर्ष में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने वक्ताओं का स्वागत करते हुये बताया कि वक्ताओं में बिजली और रेलवे में संघर्षरत मज़दूरों के प्रतिनिधियों सहित एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर भी शामिल हैं तथा देशभर से और विदेशों से भी सैकड़ों सहभागी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं।

सहभागियों में किसानों, मज़दूरों, युवाओं और महिलाओं सहित, विभिन्न पेशों से जुड़े लोग शामिल हैं। इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों से मज़दूरों और किसानों की यूनियनों के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय प्रवासी मज़दूरों के कार्यकर्ता भी शामिल हुये थे।

श्री बिरजू नायक ने विस्तार से बताया कि कृषि पर बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीवादी घरानों के वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। कृषि के लिए ज़रूरी सभी वस्तुओं – बीजों, उर्वरक, बिजली, फसलों की ख़रीद कीमतों और किसानों को उनकी उपज के लिए मिलने वाले मूल्य तथा बाज़ार

में उत्पादों की कीमतों तक पर इजारेदारों का वर्चस्व बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बड़े इजारेदार पूंजीवादी कॉरपोरेट घरानों के पास बड़े पैमाने पर भंडारण और परिवहन की सुविधाएँ हैं और हकीकत में, वे उन सभी कीमतों को निर्धारित कर सकते हैं, जिन कीमतों पर कृषि-उत्पादों को बाज़ार में ख़रीदा और बेचा जाता है। वे हिन्दोस्तान में ख़रीदे गए इन कृषि उत्पादों को और भी अधिक कीमत पर विश्व बाज़ार के लिये निर्यात कर सकते हैं और इससे अत्यधिक मुनाफ़े बना सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण के ज़रिये, इस हकीकत को समझाया कि सरकार बड़े से बड़े पूंजीपतियों के हित में काम करती है। सरकार ने 13 मई को अचानक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और इस प्रतिबंध के चलते गेहूं के अधिकांश निर्यातकों पर पाबंदी लग गई, लेकिन, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को उस तारीख से पहले ही एक बैंक गारंटी जारी की गई थी ताकि वह जल्दी से जल्दी हिन्दोस्तान का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक बन सके।

श्री बूटा सिंह बुर्ज गिल ने पिछले 3-4 दशकों में हिन्दोस्तान में कृषि के बढ़ते संकट को समझाने के लिए वस्तु स्थिति से जुड़े कई तथ्य प्रस्तुत किए, जिनके कारण वर्तमान संकट पैदा हुआ है। उन्होंने बताया कि हरित-कांति ने देश को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सक्षम बनाया और इससे कृषि मज़दूरों की

श्री बूटा सिंह बुर्ज गिल ने पिछले 3-4 दशकों में हिन्दोस्तान में कृषि के बढ़ते संकट को समझाने के लिए वस्तु स्थिति से जुड़े कई तथ्य प्रस्तुत किए, जिनके कारण वर्तमान संकट पैदा हुआ है। उन्होंने बताया कि हरित-कांति ने देश को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सक्षम बनाया और इससे कृषि मज़दूरों की

शेष पृष्ठ 2 पर

रेलवे के ट्रेकमैनों का दिल्ली में विशाल विरोध प्रदर्शन

28 सितम्बर, 2022 को आल इंडिया रेलवे ट्रेक मैटर्नर्स यूनियन (ए.आई.आर.टी.यू.) की अगुवाई में हजारों की संख्या में आये, रेलवे के ट्रेकमैनों ने अपनी मांगों को लेकर नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में भारतीय रेल के 17 मंडलों से लगभग ढाई हजार से ज्यादा महिला और पुरुष ट्रेकमैन शामिल हुए। प्रदर्शन का संचालन संगठन के महामंत्री श्री राकेश चंद्र वर्मा ने किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता श्री नरेंद्र पांचाल सहित 17 मंडलों से आए ट्रेकमैनों ने की।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, ए.आई.आर.टी.यू. के पदाधिकारियों ने घोषणा की कि ट्रेकमैनों के संघर्ष में यह प्रदर्शन ऐतिहासिक साबित होगा।

पदाधिकारियों ने लवासा कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि हर महीने ड्यूटी के दौरान 40 ट्रेकमैनों की मौत हो जाती है। साल में लगभग 500 ट्रेकमैनों की मौत होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा, जहां ड्यूटी के दौरान इतनी बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। केन्द्र सरकार यह दावा करती है कि भारतीय रेल विश्व स्तर की सुरक्षित रेल यात्रा प्रदान करती है। लेकिन रेल यात्रा को सुरक्षित करने वाले लाखों ट्रेकमैनों के जीवन की सुरक्षा करने में सरकार असफल रही है।



विभिन्न मंडलों से आए ट्रेकमैनों ने काम के दौरान आने वाली अपनी मुश्किलों को बताते हुए कहा कि भारतीय रेल प्रशासन ट्रेकमैनों पर अत्यधिक काम का दबाव डाल रहा है। हमें अपने जायज़ अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हमें अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। हमें अधिकारियों के निजी घरेलू कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। हमारे साथ गाली-गलौच व मारपीट होना आम बात है। यदि हम अपने अधिकारों की या नियम और कानून की बात करते हैं तो हमें दंडित करने के लिए झूठी चार्जशीट पकड़ा दी जाती है और परेशान किया जाता है।

उन्होंने कहा कि ट्रेकमैनों को इंजीनियरिंग गेटों पर गेटमैन की ड्यूटी दी जाती है। लगातार 12 घंटे की ड्यूटी होती है। गेट पर बने छोटे से कमरे में रोशनी, पानी व शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। रेल प्रशासन को इसका आभास नहीं है कि गेटमैन की ड्यूटी एक इंसान कर रहा है, जिसे प्यास भी लगती है, शौचालय की आवश्यकता भी पड़ती है। मज़दूर एकता कमेटी की एक टीम ने रेलवे ट्रेकमैनों के समर्थन में, प्रदर्शन में भाग लिया। मज़दूर एकता कमेटी की ओर से ट्रेकमैनों के संघर्ष के समर्थन में एक पर्चा जारी किया, जिसका आंदोलित ट्रेकमैनों ने बहुत स्वागत किया।

मज़दूर एकता कमेटी की ओर से संतोष कुमार ने कहा कि हमारा संगठन भारतीय रेल के ट्रेकमैनों के साथ भी खड़ा है। आपका जु़ज़ार संघर्ष देश के सभी मज़दूरों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत है। हम आपके संघर्ष की जीत की पूरी कामना करते हैं। हम आपकी जायज़ मांगों का समर्थन करते हैं। मज़दूर एकता कमेटी सरकार से मांग करती है कि ट्रेकमैनों की मांगों को बिना शर्त पूरा करे और भारतीय रेल में किये जा रहे निजीकरण पर तुरंत रोक लगाए।

धरने को संबोधित करने वालों में थे – श्री कांता राजू (राष्ट्रीय महामंत्री), श्री राम नरेश पासवान (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष), पंकज राजपूत (राष्ट्रीय सहायक महामंत्री, सह संचालक), श्री राजेंद्र कौशिक (राष्ट्रीय सहायक महामंत्री), श्री रवि यादव (अध्यक्ष इलाहाबाद मंडल), श्री शुभम उपाध्याय (मीडिया प्रभारी बिलासपुर), उपेन्द्र यादव (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), राजेश मौर्या (मंडल

शेष पृष्ठ 3 पर

अंदर पढ़ें

- राडियो टेप्स से किस बात का पर्दाफाश हुआ 3
- पाठकों की प्रतिक्रिया 3

कृषि का संकट और समाधान

पृष्ठ 1 का शेष

स्थिति में भी सुधार हुआ। हालांकि, इसने उन फ़सलों को बढ़ावा दिया, जिनके लिये अधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, ऐसी फ़सलों को प्राथमिकता दी गयी जिनमें कीड़ों और बीमारियों का खतरा अधिक होता है। इसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता भी नष्ट हो गयी और इसने कई फ़सलों को पैदा करने की क्षमता को भी बर्बाद कर दिया। कई किसानों ने यह सपना देखा था कि हरित क्रांति से उन्हें अधिक लाभ होगा। लेकिन हरित क्रांति ने कृषि के संकट को हल करने की बजाय पंजाब में कृषि और किसानों को बरबाद और नष्ट कर दिया।

केंद्र सरकार ने तीन किसान-विरोधी कानून लाने की कोशिश की थी, जिनके द्वारा कृषि पर हिन्दोस्तानी और विदेशी कॉर्पोरेट घरानों की पकड़ को और मजबूत किया जा सके। हमने एक साल से भी अधिक समय तक कड़ा संघर्ष किया और पूरे पंजाब और अन्य राज्यों में किसानों को संगठित किया। हम अपने संघर्ष की बदौलत सरकार को कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करने में सफल भी रहे। लेकिन सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर हमारे आंदोलन को वापस लेने की शर्त के रूप में जो आश्वासन दिए थे, उनमें से हमारी किसी भी मांग को सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। ऐसे हालातों में हमें फिर से आंदोलन करना होगा। संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमें संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) को मजबूत करना होगा।

उन्होंने बताया कि किसानों के लिए कर्ज राहत, उनकी एक प्रमुख मांग है। कृषि के लिए राज्य को एक समग्र योजना बनाने की आवश्यकता है कि – किस जगह पर कितना और क्या उगाया जाना है, राज्य की खरीद एजेंसियां किस कीमत पर उपज को खरीदेंगी, भंडारण तथा परिवहन और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कैसी होगी, आदि। केवल एम.एस.पी. की बात करना ही काफी नहीं है, क्योंकि इस समय एम.एस.पी. सिर्फ गेहूं और धान के लिए ही दी जा रही है, सरकार द्वारा अन्य सभी कृषि उत्पादों को भी लाभकारी कीमतों पर खरीदने की आवश्यकता है। जब तक ऐसे क़दम नहीं उठाए जाते, कृषि के संकट का समाधान नहीं हो सकता। बूटा सिंह बुर्ज गिल ने किसानों के साथ मज़दूर वर्ग की मजबूत एकता के लिए एक ज़ोरदार अपील की। यदि कृषि और उद्योग मिलकर पूरे समाज की भलाई के दृष्टिकोण से काम करें, तभी हम इस संकट के समाधान की आशा कर सकते हैं।

मीटिंग को संबोधित करते हुए श्री शैलेन्द्र दूबे ने उस लड़ाकू संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो संघर्ष विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को वर्तमान स्वरूप में संसद में पेश होने से रोकने के लिए पूरे देश में विजली इंजीनियरों और कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। विधेयक का उद्देश्य है राज्य के डिस्कॉम के वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल करके निजी कंपनियों को विजली वितरण पर कब्ज़ा करने के लिए सक्षम बनाना। इजारेदार पूंजीवादी घरानों के बढ़ते प्रभुत्व पर भी प्रकाश डाला। पूंजीवादी घरानों का यह प्रभुत्व एक तरफ किसानों को तबाह कर रहा है और दूसरी तरफ शहरों में मज़दूरों के बीच बढ़ती भुखमरी से उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है।

उन्होंने बताया कि किसानों के लिए इस विजली संशोधन विधेयक के विनाशकारी परिणाम होंगे। क्योंकि सिंचाई के लिये अपने पंप सेट और अन्य कृषि मशीनरी के संचालन के लिए विजली का खर्च नहीं उठा सकेंगे, उन्हें अत्यधिक कर्ज, दिवालियेन और बर्बादी की ओर धकेल दिया जाएगा। किसानों के संघर्ष को सांझा करते हुए, उन्होंने कृषि की लागत वस्तुओं पर अधिक से अधिक राज्य सब्सिडी की मांग की। उन्होंने विजली संशोधन विधेयक को किसान-विरोधी, समाज-विरोधी घोषित करते हुए, विधेयक को वापस लेने की मांग के साथ एकजुट होकर, संगठित संघर्ष करने का आहवान किया। उन्होंने घोषणा की कि पूरे देश के विजली कर्मचारी अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, 23 नवंबर को नई दिल्ली में एक विशाल विरोध प्रदर्शन में एक साथ आएंगे।

प्रोफेसर वी. सेठ ने कृषि के संकट को समझाने और उसके समाधान का प्रस्ताव पेश करने के लिए पावर-प्लाइंट प्रस्तुति पेश की। उन्होंने कहा कि इस संकट के दो पहलू हैं। अधिकांश किसान सम्मानजनक जीवन यापन के लिए कृषि उत्पादों से पर्याप्त आमदनी अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही शहरों में मज़दूरों का एक बहुत बड़ा तबका, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन को जुटा पाने में असमर्थ हैं। एक किसान परिवार की औसत आय 5,000 रुपये प्रति माह से कम है। उन्होंने बताया कि इन हालातों के कुछ प्रमुख कारण हैं – बीज, उर्वरक, डीजल, विजली, आदि जैसे कृषि के लिये आवश्यक लागत वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, किसानों द्वारा उपजाये गये कृषि उत्पादों के लिए खरीद मूल्य बहुत ही कम है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की कमी और अधिकांश किसानों पर कर्ज का बढ़ता बोझ है। उन्होंने बहुप्रचारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ. बी.वाई.) का पर्दाफाश करते हुये बताया कि इसका उद्देश्य है किसानों को राहत पहुंचाने के बहाने निजी बीमा कंपनियों को भारी मुनाफ़ा कमाने में सक्षम बनाना।

प्रोफेसर वी. सेठ ने पूरी कृषि प्रक्रिया पर हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीवादी घरानों के बढ़ते प्रभुत्व पर भी प्रकाश डाला। पूंजीवादी घरानों का यह प्रभुत्व एक तरफ किसानों को तबाह कर रहा है और दूसरी तरफ शहरों में मज़दूरों के बीच बढ़ती भुखमरी से उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है।

श्री संजय पांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि सरकारी नीतियां बहुसंख्य लोगों के हित में काम नहीं करती हैं, चाहे वे शहरों में हों या गांवों में। इन नीतियों का उद्देश्य, किसानों और मज़दूरों, दोनों को लूटकर अपनी तिजोरियों को भरने में बड़े कॉरपोरेट घरानों को सक्षम बनाना है। उन्होंने सुझाव दिया कि कैसे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े मज़दूर और विशेषज्ञ, किसान यूनियनों को पेशेवर सहायता प्रदान कर सकते हैं। भारतीय रेल में इंजन चालकों की यूनियन के एक कार्यकर्ता के रूप में, जो रेलवे के निजीकरण के सरकार के प्रयासों का जुझारु विरोध कर रहे हैं, उन्होंने मज़दूरों और किसानों के एकजुट संघर्ष का आहवान किया।

मुख्य वक्ताओं के विचार प्रस्तुत हो जाने के बाद, चर्चा में दस से अधिक सहभागियों ने अपनी बातें रखीं। तमिलनाडु से वर्कर्स यूनिटी मूवमेंट के प्रतिनिधि ने, संसद में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की पकड़ से मुक्त होने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो हमें विभाजित करने और झूठे वादे करके हमें बेवकूफ बनाने के इरादे से काम करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टियां इजारेदार पूंजीवादी घरानों के मुनाफ़ों को अधिकतम करने के लिए लगातार काम करती आयी हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण के अपने एजेंडे के इर्द-गिर्द मज़दूरों और किसानों की एकता बनाने का आहवान किया। जिसमें कॉरपोरेट घरानों का मुनाफ़ा नहीं, बल्कि पूरे समाज का कल्याण सर्वोपरि होगा।

राजस्थान में किसान मज़दूर व्यापारी संघर्ष समिति से जुड़े हुनुमान प्रसाद शर्मा ने कृषि के संकट पर विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि मज़दूरों और किसानों के लिए एकमात्र समाधान अपने एक ही दुश्मन, इजारेदार कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ एकजुट होना है, जिन घरानों के खुदगर्ज हितों की रक्षा हिन्दोस्तानी राज्य करता है। मज़दूरों और किसानों को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो सभी को सुख और सुरक्षा की गारंटी दे सके।

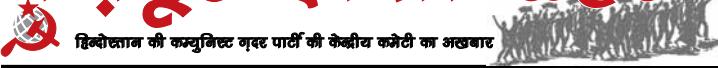
गदर इंटरनेशनल, ग्रेट-ब्रिटेन के सलविंदर डिल्लों ने बताया कि ब्रिटेन में मज़दूरों और हिन्दोस्तान में किसानों और मज़दूरों का संघर्ष, सबसे बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों की पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष है। उन्होंने आहवान किया कि इस संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता, मज़दूरों और किसानों के हाथों में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के संघर्ष तेज़ करना।

कामगार एकता कमेटी के एस. दास ने मज़दूरों और किसानों का एक शक्तिशाली और एकजुट आंदोलन खड़ा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मज़दूरों और किसानों को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी। कृषि के संकट और समाज की सभी उत्पादक शक्तियों की तबाही सहित, हिन्दोस्तानी समाज के गहरे संकट को हल करने का यही एकमात्र तरीका है।

अखिल भारतीय किसान मज़दूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र पूरे समाज के हित में काम करे, इसको सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है मज़दूरों और किसानों के राज को स्थापित करने के लिए काम करना।

अन्य सहभागियों ने कृषि के सभी पहलुओं पर इजारेदारी का नियंत्रण, डेयरी किसानों की समस्याओं, बड़ते कर्ज और किसान आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं, छोटी भूमि के मालिकों की दरिद्रता और बड़ती भूमिहीनता के बारे में अपने विचार रखे। दिल्ली के एक औद्योगिक क्षेत्र के नौजवान कार्यकर्ता ने शहरों में दिहाड़ी मज़दूरों के बीच आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या पर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट का हवाला दिया। मज़दूर और किसान दोनों आजीविका की भयानक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और इसके लिए केवल पूंजीवादी व्यवस्था ही ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हम मज़दूर और किसान, जो समाज की संपत्ति पैदा करते हैं, हमें समाज का मालिक बनना होगा।

मीटिंग में हुई चर्चा का सारांश पेश करते हुए, संतोष कुमार ने वक्ताओं और सभी सहभागियों को उनकी बहुमूल्य प्रस्तुतियों और सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। इस असूल को कायम रखते हुए कि मज़दूर



To
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मध्यसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई-392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक— मध्यसूदन कस्तूरी, ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911



WhatsApp
9868811998

अवितरित होने पर हस्त पते पर वापस भेजें :
ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020

भिवंडी में करघा मज़दूरों की विजय सभा

भिवंडी में 12 सितंबर, 2022 को लालबाबटा पावर लूम वार्फर और असंगठित कामगार संघर्ष सभा के बैनर तले "कामगार संघर्ष सभा" का आयोजन किया गया था। यह सभा उन मज़दूरों की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई थी, जिन्होंने एक संयुक्त और दृढ़तापूर्ण संघर्ष के बाद अपने मासिक वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि हासिल की थी।

वक्ताओं में महाराष्ट्र के दहानू से विधायक व सीटू के राज्य सचिव, कॉमरेड विनोद निकोल और सोलापुर के पूर्व विधायक व मज़दूर नेता, कॉमरेड नरसाया एडम मास्टर थे। लोक राज संगठन (एल.आर.एस.) के एक प्रतिनिधि को भी सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

करघा मज़दूरों और बीड़ी मज़दूरों के नेता कॉमरेड सुनील चव्हाण ने मज़दूरों की एकता और उनके समर्थन की सराहना की और सभा का संदर्भ समझाया। भिवंडी में जब करघा मज़दूर उचित मज़दूरी और सुविधाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, तभी करघा मालिकों के गुंडों ने उनकी यूनियन के कार्यालय में प्रवेश किया और उन पर हमला कर दिया। परन्तु, मज़दूरों



ने एकजुट होकर गुंडों को भगा दिया और अब मालिकों के पास बातचीत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

हॉल में मौजूद 1,000 महिलाएं, पुरुष और नौजवान, कॉमरेड सुनील के साथ सहमत थे। उन्होंने "लड़ें जीतेंगे!", "इंकलाब जिंदाबाद!", "हमारा हक़ लड़के लेंगे!" और "मलिकों की दादागिरी नहीं चलेगी!", आदि जुझारू नारे लगाए। काम का दिन होने की वजह से मज़दूरी का नुकसान होने की संभावना और बारिश होने के बावजूद, इस सभा में भारी संख्या में मज़दूर शामिल हुए थे।

कॉमरेड नरसाया एडम मास्टर ने गुंडों से लड़ने वाले 400 मज़दूरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम हमेशा जीतेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे हैं; हम अपना पसीना बहाते हैं। जो कुछ भी पैदा होता है वह मेहनतकशों के श्रम के कारण होता है। हम मालेगांव, नासिक, सोलापुर, आदि अनेक इलाकों में संघर्ष कर रहे हैं।

लोक राज संगठन की प्रतिनिधि सुश्री तृप्ति ने बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और मज़दूरों की उपस्थिति की

सराहना की और कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हमें न्यूनतम मज़दूरी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की मांग के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। क्या इसी आजादी के लिए हमारे पूर्वज लड़े थे? यह वह समाज नहीं है जिसे हम चाहते हैं। आज हर वस्तु के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। हमारी सार्वजनिक संपत्तियों को सर्ते में सबसे अमीरों को बेचा जा रहा है। उनके पास हिन्दूस्तान के मेहनतकशों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने अधिकारों के लिए किये गये मज़दूरों के इस संघर्ष के लिये लोक राज संगठन का समर्थन व्यक्त किया।

कॉमरेड निकोल ने कहा कि वे हमें हिंदू और मुस्लिम के रूप में बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मज़दूरों के संघर्ष के लिए अपने समर्थन की घोषणा की और कहा कि वे इसके बारे में भिवंडी के विधायक से बात करेंगे और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे कि ट्रेड यूनियनों, उनके नेताओं और मज़दूरों पर हमले कैसे हो रहे हैं।

<http://hindi.cgpi.org/22624>



पाठकों की प्रतिक्रिया

प्रिय संपादक,

11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी के अवसर पर प्रकाशित लेख सटीकता से दर्शाता है कि "संयुक्त राज्य अमरीका वही राज्य है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, सर्व-सम्मति से स्थापित किये गए, राज्यों के आपसी संबंधों के हर नियम और मानदंड का बार-बार उल्लंघन किया है।"

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से अमरीका द्वारा आयोजित युद्धों, सशस्त्र हस्तक्षेपों और तख्तापलट की कार्यवाइयों की सूची में नीचे दे रहा हूं। मैं मानता हूं कि यह सूची भी शायद संपूर्ण नहीं है।

- ◆ 1946 : अमरीका ने फिलीपींस और दक्षिण कोरिया पर कब्जा किया।
- ◆ 1947 : फासीवाद विरोधी ताक़तों को दबाने के लिए अमरीका ने सशस्त्र बलों को यूनान में उतारा।
- ◆ 1948-49 : अमरीकी सेना ने चीन के मुक्ति संग्राम में हस्तक्षेप किया और ताइवान की स्थापना में मदद की।
- ◆ 1949 : अमरीकी खुफिया ऐजेंसी सी.आई.ए. ने सीरिया में तख्तापलट आयोजित किया।
- ◆ 1950-53 : कोरियाई युद्ध को चलाया।
- ◆ 1953 : अमरीकी खुफिया ऐजेंसी सी.आई.ए. ने ईरान में तख्तापलट आयोजित किया।
- ◆ 1954 : अमरीका ने ग्वाटेमाला पर

अमरीकी साम्राज्यवादियों के अपराध

- आक्रमण किया और वहां कठपुतली शासन स्थापित किया।
- ◆ 1955-75 : वियतनाम पर युद्ध किया।
- ◆ 1961 : बे ऑफ पिरेस का क्यूबा पर आक्रमण।
- ◆ 1962 : थाइलैंड में कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए अमरीकी नौसैनिकों को तैनात किया।
- ◆ 1965 : अमरीकी सेना ने डोमिनिकन गणराज्य पर कब्जा किया।
- ◆ 1965-67 : इंडोनेशिया में अमरीकी सशस्त्र फासीवादी शासन स्थापित किया, जिसने लाखों कम्युनिस्टों को मार डाला।
- ◆ 1973 : योम किप्पुर युद्ध में अमरीका ने इज़रायल की सहायता की।
- ◆ 1973 : सी.आई.ए. ने चिली में एक सैन्य तख्तापलट का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रपति ओलेंदे की मृत्यु हो गई।
- ◆ 1979-88 : सी.आई.ए. ने अफगानिस्तान में छद्म युद्ध छेड़ा।
- ◆ 1981-86 : सी.आई.ए. ने निकारागुआ में छद्म युद्ध छेड़ा।
- ◆ 1988 : अमरीकी सेना ने पनामा पर कब्जा किया।
- ◆ 1991-93 : ईरान पर हमला करने के लिये अमरीका ने ईराक को हथियारों से लैस किया।
- ◆ 1994 : अमरीका ने हैती पर आक्रमण किया।

- ◆ 1995 : अमरीका के नेतृत्व में नाटो ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर बमबारी की।
- ◆ 1998 : ईराक पर अमरीकी बमबारी तथा अफगानिस्तान व सूडान पर मिसाइली हमले।
- ◆ 1999 : कोसोवो के युद्ध में अमरीकी हस्तक्षेप।
- ◆ 2001-21 : अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला और कब्जा किया।
- ◆ 2002 के बाद : अमरीका ने यमन में सऊदी हस्तक्षेप का समर्थन किया; पाकिस्तान में ड्रोन हमले किये।
- ◆ 2003 के बाद : अमरीका ने ईराक पर हमला करके कब्जा कर लिया; सद्दाम हुसैन की हत्या कर दी।
- ◆ 2007 : सोमालिया में अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप।

इसमें कोई शक नहीं है कि अमरीकी साम्राज्यवाद राज्यों के आपस बीच सभ्य संबंधों और राष्ट्रीय संप्रभुता के सभी स्वीकृत मानदंडों का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता है। यह युद्ध करके और दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करके पनपता है। यह विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है।

आपका,

मुकुंद, विजयवाड़ा

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्कैन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम—लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या—20066800626,
ब्रांच नं.—00974, IFSC Code: MAHB0000974, मो.—9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.—9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

